THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) No, Sir.

(b) The words 'Office of Development Commissioner Handicrafts, New Delhi' in part (a) of Unstarred Question No. 2449 answered on 15.3.1993, had been inadvertantly construed to refer to Headquarters Office of the Office of Development Commissioner (Handicrafts) at New Delhi, and therefore, the answer covered the vacancies in Headquarters Office only.

(c) A statement is attached.

[See APPENDIX CLXVI, Annexure No. 65]

Generation of employment for handloom weavers

4079. SHRI PRAGADA KOTAIAH:
SHRI RAM NARESH YADAV:
PROF. I. G. SANADI:
SHRI SATYANARAYANA DRONAMRAJU:
SHRI MUTURU HANUMANTHA RAO:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the schemes which have been formulated to help handloom weavers from out of the funds earmarked for generation of employment under the Ministry of Rural Development; and

(b) whether any scheme has been formulated to provide continous and full employment to handloom weavers?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) Handloom is covered under the ongoing Rural Development Programmes of Ministry of Rural Development like Integrated Rural Development Programme.

(b) A-part from the schemes of Ministry of Rural Development Ministry of Textiles has a number of ongoing schemes for improving employment opportunities of handloom weavers. These schemes include Janata Cloth Scheme, MDA Scheme and Project Package Scheme.

सूत की उत्पादन क्षमता

4080. **श्री राम जेठमलानी :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपास की बजाय सूत निर्यात करके 80 प्रतिशत अधिक विदेशी मुद्रा, सूत की बजाय कपड़े का निर्यात करके 50 प्रतिशत अधिक विदेशी मुद्रा तथा कपड़े की बजाय सिले-सिलाये वस्त्रों का निर्यात करके 220 प्रतिशत अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित किये जाने की संभावना होती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार देश में कपास के बढ़ते हुये उत्पादन के अनुसार सूत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिये सतत प्रयास कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सूत की कितनी मात्रा के लिये उत्पादन क्षमता स्थापित कर दी जायेगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) यह सही है कि अपरिष्कृत कपास के बजाय यार्न, फैब्रिक, परिधान आदि जैसे माध्यमिक उत्पाद तथा अंतिम उत्पादों का निर्यात करके अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने की संभावना है । मूल्यवर्धन का प्रतिशत मद की किस्म तथा निर्यात की गई मदद संबंधी निष्पादित विभिन्न प्रक्रियाओं पर निर्भर होगा ।

(ख) और (ग) उदारीकृत औद्योगिक नीति के अन्तर्गत उद्यमी औद्योगिक

नीति में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अध्याधीन-लाइसेंस की अपेक्षा के बिना कताई एकक स्थापित करने के लिये स्वतंत्र हैं।

कपड़ा मिलों की सूत उत्पादन क्षमता

4081. डा० जितेन्द्र कुमार जैन :
श्री राम जेठमलानी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत कार्यरत मिलों में सूत का उत्पादन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इन मिलों की सूत उत्पादन की वार्षिक स्थापित क्षमता कितनी है ;

(ग) क्या इन मिलों की स्थापित क्षमता का पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो वर्ष 1990–91, 1991–92 और 1992–93 में कितने सूत का उत्पादन किया गया और कितने प्रतिशत उत्पादन क्षमता का उपयोग किया गया ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1991–92 के दौरान यार्न उत्पादन के संबंध में एन०टी०सी० मिलों की स्थापित क्षमता 37.34 लाख तकुए थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) वर्ष 1990–91 से 1992–93 (अनन्तिम) तक की अवधि के दौरान एन०टी०सी० मिलों द्वारा निर्मित यार्न के ब्यौरे और उपयोग में लाई गई क्षमता का प्रतिशत नीचे दिया गया है:–

वर्ष	कुल यार्न उत्पादन कि०ग्रा०	क्षमता उपयोग (%)
1990–91	173.95	66.2
1991–92	159.42	60.5
1992–93 (अनन्तिम)	117.00	47.5

Area based projects for welfare of handloom weavers

4082. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to refer to answer to Unstarred Question 2429 given in the Rajya Sabha on the 15th March, 1993 and state:

(a) whether Government propose to promote area-based project specific programme for the welfare of weavers and for development of identified handloom products;

(b) if so, the details of such programme and the areas identified for purpose; and

(c) the number of weavers likely to be benefitted under the programme, State-wise?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) Yes, Sir

(b) Projects are sanctioned under Project Package Scheme on receipt of comprehensive and viable proposals from the State Governments. Such projects may have one or more of the following objectives, namely, development of a particular product benefit a particular area and benefit a particular target group. This is an on going Scheme. So far under the Scheme projects have been sanctioned in the